



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 111-2026/Ext.]

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2026
(29 आषाढ़, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग—II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग—III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 34/के०अ० 32/2012/धा० 28/2026, दिनांक 17 जनवरी, 2020— हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 7/के०अ० 32/2012/ धा० 28/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 में संशोधन करने बारे।	265—266
भाग—IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग—III**हरियाणा सरकार**

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई, 2026

संख्या का०आ० 34/के०अ० 32/2012/धा० 28/2026.— लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 32) की धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय मुख्य न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 7/के०अ० 32/2012/धा० 28/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 7/ के०अ० 32/2012/धा० 28/2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 में, तृतीय पैरा में, आठवीं पंक्ति में, "वित्तीय वर्ष (2019—2020 से 2022—2023) के लिए" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा चिह्नों का लोप कर दिया जाएगा तथा प्रथम अप्रैल, 2023 से लोप किया गया समझा जाएगा।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT****Notification**

The 20th July, 2026

No. S.O. 34/C.A 32/2012/S. 28/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 28 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 32 of 2012), the Governor of Haryana, in consultation with the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. S.O. 7/C.A.32/2012/S.28/2020, dated the 17th January, 2020, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. S.O. 7/C.A.32/2012/S.28/2020, dated the 17th January, 2020, in third para, in the seventh line, the words, brackets, figures and sign “financial year (2019-2020 to 2022-23)” shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st April, 2023.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.